28-10-26 VNS PG-3 FRONT PAGE-ALLA.qxd 27-10-2026 22:26 Page 1



आज

भूखे शेरकी तरह दहाड़े

लगी रेकार्ड की झड़ी

अभिषेक

प्रयागराज, बुधवार २८ अक्तूबर, २०२६ सौर ११, कार्तिक कृष्ण ३, २०८३ वि.। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज (रीवा संस्करण), कानपुर (झांसी संस्करण), लखनऊ, आगरा, बरेली, हल्द्वानी,पटना (कोलकाता संस्करण), रांची (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित नगर संस्करण पृष्ठ १२, मूल्य ३.०० रुपये



वाराणसीके लिए २६.८९ करोड़की सीवर-पेयजल परियोजनाको मंजूरी

योगी कैबिनेट ने २२ प्रस्तावों पर लगायी मुहर, चार औद्योगिक परियोजनाओं को भी मिली स्वीकृति



लखनऊ (आससे)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। कैबिनेट ने पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए। किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़े प्रस्तावों को विशेष प्राथमिकता दी गयी। प्रदेश कैबिनेटने वाराणसीमें २६.८९ करोड़की सीवेज और पेयजलसे जुड़ी विकास परियोजनाको मंजूरी दे दी है। कैबिनेटकी स्वीकृतके बाद अब शहरके पुराने और विस्तारित क्षेत्रोंमें टेण्डर प्रक्रिया और निर्माण कार्यका रास्ता साफ हुआ। कैबिनेटके महत्वपूर्ण निर्णयसे तीन प्रमुख जोन लहरतारा, (शेष पृष्ठ ११ पर)

१०४.२८ करोड़ की लागतसे स्थापित होगा साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र

लखनऊ (आससे)। उत्तर प्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 104.28 करोड़ की लागत से साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के साइबर सुरक्षा नवाचार केंद्र के जरिये उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा परिचालन (शेष पृष्ठ ११ पर)

यूपी : विधान परिषद चुनावमें सपाको वाराणसीमें भारी बढ़त

लखनऊ (आससे.)। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह से जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरे व वीडियोग्राफी की निगरानी में मतगणना कराई जा रही है। प्रारंभिक रुझान में भारतीय जनता पार्टी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, बरेली में आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी गोरखपुर और आगरा में आगे है। अंतिम परिणाम तक उलटफेर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की 11



भाजपाको शिक्षक मेरठ, बरेलीमें बढ़त, आगरामें सपा आगे, कड़ी सुरक्षाके बीच मतगणना जारी

विधान परिषद सीटों के लिए लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और गोरखपुर में सुबह आठ बजे से काउंटिंग हो रही है। सबसे पहले मतपत्रों के बंडल बनाने का काम पूरा होने के बाद मतों की गिनती शुरु की गयी और मेरठ से पहला रुझान भी आ गया। मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्रीश चंद्र शर्मा अपने प्रतिद्वंद्वी से लगभग 2500 वोटों से आगे हैं जबकि लखनऊ में शिक्षक क्षेत्र से उमेश द्विवेदी आगे हैं। वहीं आगरा में शिक्षक चुनाव में पहले चक्र में सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल एक हजार वोट से आगे हैं। गोरखपुर में शिक्षक क्षेत्र से सपा के ही संजयन त्रिपाठी और वाराणसी में शिक्षक क्षेत्र से लाल बिहारी यादव (शेष पृष्ठ ११ पर)

निर्वाचन आयोगका हलफनामा 'कपटपूर्ण'

नयी दिल्ली (आससे)। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल हलफनामा 'भ्रामक और कपटपूर्ण'

एसआईआरपर एकतरफा लिये गये फैसले-कांग्रेस



है तथा यह खुद आयोग की साख के लिए बहुत नुकसानदेह है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह दावा भी किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग ने तथ्यों को लेकर 'शब्दों का खेल' खेला है तथा उसके फैसले सर्वसम्मति से नहीं, बल्कि एकतरफा लिए गये।

उन्होंने दावा किया कि आयोग ने फॉर्म-6 से जुड़े नये घोषणा पत्र को लेकर पहले कहा था कि इसे उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है, लेकिन बाद में शीर्ष अदालत ने इस दावे का खंडन किया। रमेश ने कहा कि आयोग अब दावा कर रहा है कि नया घोषणा पत्र अलग है और फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन फॉर्म-6 जमा करने के लिए इस घोषणा पत्र को भरना अनिवार्य था और इस कारण (शेष पृष्ठ ११ पर)

रामलीला मैदानकी अनुमतिपर कांग्रेस और दिल्ली पुलिस आमने-सामने

नयी दिल्ली (आससे)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान को लेकर कांग्रेस और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रामलीला मैदान में रैली की अनुमति वापस लेने का दावा किया, जबकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, कांग्रेस को 25 अक्टूबर (शेष पृष्ठ ११ पर)

ज्ञानेशके इस्तीफे तक जारी रहेगा संघर्ष-राहुल



नयी दिल्ली (आससे.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक वह इस्तीफा नहीं देते, तब तक विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाता रहेगा। राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आयोजित 'जन सुनवाई' में लोगों की समस्याएं सुनीं और मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाकर उनके मतदान के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि चार बूथों से 416 मतदाताओं के नाम कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से हटाए गए हैं। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से (शेष पृष्ठ ११ पर)

एनटीए ने परीक्षा के लिए शहर चुनने के नियमों में किया बदलाव

नयी दिल्ली (आससे)। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2027 परीक्षा के लिए शहर चुनने के नियमों में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी केवल अपने स्थायी या वर्तमान पते वाले राज्य के परीक्षा शहर का चयन कर सकेंगे। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यदि उम्मीदवारों के वर्तमान और स्थायी पते वाले राज्य में चार से कम परीक्षा शहर उपलब्ध हैं, तो उन्हें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर दूसरे राज्य का शहर चुनने का अवसर दिया जा सकता है। विदेश में रहने वाले या विदेशी अभ्यर्थियों के लिए भी शहर का चयन उनके पते के आधार पर ही होगा, हालांकि उन्हें भारत का कम से कम एक परीक्षा शहर चुनना अनिवार्य रहेगा। एनटीए ने यह भी साफ किया है कि किसी शहर में परीक्षार्थियों की संख्या बहुत कम रहने पर शहरों का विलय किया जा सकता है और केंद्र आवंटन पर एजेंसी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। बिहार में इस बार जेईई मेन का आयोजन 11 शहरों में किया जाएगा। इनमें पटना, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, गयाजी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर और सारण में केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन भरते समय शहर का नाम और उसका संबंधित कोड ध्यान से जांच लें। खासकर बिहार और महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के बीच भ्रम की स्थिति से बचने के लिए बिहार के औरंगाबाद केंद्र का चयन करते समय कोड क्रक01 जरूर जांचना होगा

कोल्ड स्टोरेज, स्वच्छता-वैधता अवधि की जांच, छहका लाइसेंस निलंबित

लखनऊ (आससे.)। प्रदेश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए घरों तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने खाद्य सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स पर प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की व्यापक पड़ताल की। ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन, रिलायंस और मेट्रो सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छता, तापमान नियंत्रण, कोल्ड स्टोरेज, वैधता अवधि, लेबलिंग और लाइसेंस संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की गई। अभियान के दौरान कुल 218 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई। मानकों में कमियां मिलने पर 154 सुधार नोटिस जारी किए गए, 6 स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर सुधार होने तक कारोबार बंद कराया गया और जांच के लिए 11 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। इसके अलावा दो स्टोर्स में फ्रोजन मीट एवं मीट उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई, जबकि आगरा में लेबल संबंधी अनियमितताओं के चलते मखाने के 273 पैकेट, जिनका अनुमानित मूल्य 68 हजार रुपये है, सीज किए गए।लखनऊ में चिनहट स्थित जेप्टो स्टोर के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

सुप्रीमकोर्टने एसआईआरपर कहा-हमें सब पता, जांच करेंगे



नयी दिल्ली (आससे)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्क्रूक्र और चुनाव आयोग के कामकाज पर दायर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप 10 दिन में चुनाव आयोग के हलफनामे का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर तय की। दरअसल, याचिकाकर्ताओं की

याचिकाकर्ता १० दिनमें दें जवाब

ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपील की थी कि चुनाव आयोग ने सोमवार को ही अपना जवाब दिया है। हमें जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। सिंघवी ने दलील दी कि कोर्ट फिलहाल (शेष पृष्ठ ११ पर)

फिर जेल जायेंगे आसाराम, सुप्रीम-कोर्टका पैरोल बढ़ानेसे इनकार

जयपुर (एजेंसी)। जोधपुर में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम की पैरोल को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। साथ ही आसाराम को निर्देश दिया कि वह आज (मंगलवार) शाम पांच बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करने को कहा। हालांकि अभी तक आसाराम ने सरेंडर नहीं किया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह आसाराम की सेहत का ध्यान रखें। दरअसल, आसाराम 20 दिन की मेडिकल पैरोल पर बाहर है, जिसे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

एमएलसी चुनावमें भाजपा कर रही बेईमानी-अखिलेश

लखनऊ (आससे)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद



चुनाव में सपा प्रत्याशी कांति सिंह की सीट पर मतदान को लेकर सवाल उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि 97 बूथों पर बिना फोल्ड किये हुए वोट मिले हैं। अखिलेश ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा डिब्बा वोट डालकर लाया गया होगा। उन्होंने भाजपा पर चुनाव में बेईमानी कराने का आरोप लगाया। वहीं, धर्मेंद्र कश्यप ने पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कश्यप समाज के एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है और इन घटनाओं में जाति विशेष के लोगों का हाथ है। धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि आज अखिलेश यादव जरूरी हैं और वह समाजवादी (शेष पृष्ठ ११ पर)

रोहतासमें दिनदहाड़े तीन करोड़ की सोना- चांदी की लूट

डेहरी ऑन सोन (आससे.)। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में सोमवार को दिनदहाड़े महात्मा गांधी चौक के समीप कंचन ज्वेलर्स की दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने भय दिखाकर तीन करोड रुपए के सोना -चांदी के आभूषण और दो लाख नकद लूट लिया। दोपहर अपाचे मोटरसाइकिल से सवार चार नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने कंचन ज्वेलर्स में धावा बोलकर दुकान मालिक अविनाश कुमार वर्मा और वहां मौजूद करीब छह कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लूट का अंजाम देकर फरार हो गए।

हटेंगे तीन सालसे तैनात अधिकारी-चुनाव आयोग

नयी दिल्ली (आससे.)। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि किसी अधिकारी को एक जिले में तीन साल से अधिक समय तक तैनात नहीं रखा जाए और गृह जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाए। निर्देशों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में किसी जिले में तीन साल की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों को भी स्थानांतरित करना होगा। गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में कार्यकाल की गणना के लिए 31 मार्च 2027 तथा उत्तर प्रदेश में 31 मई 2027 की कटऑफ तारीख तय की गई है। जिले के भीतर पदोन्नति के बाद की सेवा भी तीन साल की अवधि में शामिल होगी।

चक्रवात अर्नब को लेकर केंद्र सतर्क

नयी दिल्ली (आससे)। चक्रवात अर्नब के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क रहने, स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, मछली पकड़ने पर पूरी तरह रोक लगाने और प्रभावित इलाकों के लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों और कमजोर इमारतों से दूर रहने तथा यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। छोटी नौकाओं और मोटरबोट से आवाजाही को असुरक्षित बताया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की समुद्री चेतावनियों पर नजर रखने और आपातकालीन तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यों से स्थिति में बदलाव की जानकारी गृह मंत्रालय को देने को कहा गया है।

ब्रिक्स संसदीय मंचमें आतंकवादपर भारतका कड़ा प्रहार

नयी दिल्ली (आससे)। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच मंगलवार को संयुक्त घोषणा-पत्र अंगीकृत किए जाने के साथ संपन्न हो गया। घोषणा-पत्र में सीमापार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और दोहरे मापदंडों को समाप्त करने पर जोर दिया गया। साथ ही, वैश्विक शासन व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों का समर्थन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस मंच के संयुक्त घोषणा-पत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, देशों की संप्रभु समानता, परस्पर सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। घोषणा-पत्र में नई दिल्ली घोषणा के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का स्थायी समाधान संघर्ष और युद्ध में नहीं, बल्कि संवाद, शांति और सहयोग में निहित है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता और क्षेत्रीय संघर्षों के बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी व्यवस्था की दिशा में काम करना चाहिए, जो राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करे और सभी देशों को समान विकास के अवसर उपलब्ध कराए। बिरला ने कहा कि वैश्विक शांति का अर्थ केवल संघर्षों का अभाव नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, न्याय और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संसदीय प्रतिनिधियों से साझा चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में संसदों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे केवल कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि संवाद, आम सहमति, जवाबदेही और जनविश्वास के केंद्र हैं। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए संसदीय संस्थाओं को अधिक प्रभावी, (शेष पृष्ठ ११ पर)



यूएनएससी सुधारोंका समर्थन, संयुक्त घोषणा-पत्र में सीमापार आतंकवाद, फंडिंग-सुरक्षित ठिकानों की निंदा

हिमाचल : कांगड़ामें चिट्टा तस्करी मामले में १.०१ करोड़ की संपत्ति फ्रीज

पुलिसने घर और कारपर लगाया बोर्ड

नूरपुर (कांगड़ा) (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के खिलाफ कारवाई करते हुए नूरपुर पुलिस ने बड़ी कारवाई की। पुलिस ने इंदौरा के छन्नी गांव में 1 करोड़ 1 लाख 55 हजार 718 रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज करने संबंधी आदेश का बोर्ड लगाया है। यह कारवाई पुलिस थाना इंदौरा में वर्ष 2017 में दर्ज चिट्टा तस्करी के मामले में की गयी है। पुलिस के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की ओर से संपत्ति फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया गया। कारवाई के दौरान डीएसपी संजीव यादव और पुलिस थाना प्रभारी आशीष पठानिया सहित पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। नूरपुर पुलिस के अनुसार, फ्रीजिंग आदेश के दायरे में आने वाली संपत्तियों में आवासीय मकान, घरेलू सामान और एक कार शामिल है। इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 1,01,55,718 रुपये बताया गया है। पुलिस ने संबंधित संपत्तियों पर फ्रीजिंग आदेश की जानकारी देने वाला बोर्ड लगाया है। यह कारवाई चिट्टा तस्करी के मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत की गयी है। नूरपुर पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा कसना अभियान का अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना और नशे के कारोबार से होने वाले अवैध लाभ पर रोक लगाना है। (शेष पृष्ठ ११ पर)

यहां भी पढ़ें
-:Website:-
www.ajhindidaily.com
-:For e-Paper:-
www.ajhindidaily.com/
आज बीस साल से सेवा का संकल्प
निःशुल्क ई-पेपर सब्सक्राईब करें।

मौसम

सूर्योदय : ०६.०१
सूर्यास्त : ०५.२२

तापमान
अधि. : ३२.१
न्यून. : १९.२



